

पैरामेडिकल कार्टिसिल में घोटाला, घूस लेकर कॉलेजों को फर्जी मान्यता

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल कार्टिसिल में मान्यता के नाम पर बड़ा घोटाला उड़ागर हुआ है। सूत्रों के अनुसार, राजधानी के कुछ कॉलेजों को बिना मानकों के मान्यता दी जा रही है, जिसके बदले 2 से 3 लाख रुपये की घूस ली जा रही है। इस गोरखधंधे में कार्टिसिल के रजिस्ट्रेशन और कर्मचारियों की मिलीभगत का आरोप है जिनकारी के मुताबिक उन कॉलेजों में न तो पर्सनल स्टाफ है, न ही जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर। छात्रों की ट्रेनिंग के लिए बताए गए हाईस्टिल भी सिर्फ कागजों पर मौजूद हैं। ऐसे में पढ़ाई और ट्रेनिंग के बिना रह रहे हैं, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है तो वे बताया कि कार्टिसिल का एक कर्मचारी कालेज प्रतिनिधियों को फोन कर भोपाल कार्यालय बुलाता है, जहाँ राजस्वर में सलाकों के बाद घूस की डील फैलना होती है। ऐसे फर्जी कॉलेजों से पास होने वाले छात्रों की योग्यता पर नौकरी या इंटर्नशिप के दौरान सबाल उठते हैं, जिससे न केवल उनका करियर प्रभावित होता है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी दांव पर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई के साथ-साथ मान्यता प्रक्रिया के पारदर्शी और अनेकाना सिस्टम से नियंत्रित करना जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह के फर्जीवाड़े पर रोक लगे और छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे।

मुख्यमंत्री ने मूंग उत्पादन का 40 प्रतिशत खरीदी का लक्ष्य निर्धारित करने का क्रियान्वयन कार्यालय

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों के हित में मूंग के कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत समर्थन मूल्य पर क्रय करने का लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विषयन वर्ष 2025-26 में ग्रीष्मकालीन मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,682 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। प्रदेश में इस वर्ष मोबाइल ऐप के माध्यम से की गई गिरावरी में ग्रीष्मकालीन मूंग के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है।

रेलवे प्लेटफार्म पर दौड़ी कार

भोपाल (एजेंसी)। राजधानी के भोपाल रेलवे प्लेटफार्म पर कार और स्कूटर दौड़ रहे हैं। शनिवार तड़के ऐसे ही दो मामले समाप्त हो गए। एक कार सवारियों को लेकर प्लेटफार्म नंबर छह पर दूर तक आई। वहाँ यात्रियों को उत्तरकर लौट गई। वहाँ प्लेटफार्म नंबर पाच पर एक स्कूटर से यात्री सोती रही। यात्रियों की शिकायत के बाद एक्शन शुरू हुआ। कार मालिकों को गिरफ्तार कर उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। उनके बाहरों को जबकर लिया गया है। शनिवार को सुबह-सुबह प्लेटफार्म नंबर छह पर एक कार (एप्सी-०४ सीसी 1317) की यात्रियों को उतारते हुए देखा गया। वहाँ मौजूद यात्रियों ने इसकी बैठियों से बाहर कर सेशल मंडियों पर शेर रोक दिया। वहाँ लोगों ने रेल मदद पोर्टल विकार के जरिए रेलवे प्रशासन से इसकी शिकायत की।

भोपाल का सर्पिला ओवरब्रिज बना छादों का कारण

भोपाल (एजेंसी)। राजधानी भोपाल का सुभाष नगर रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है, लेकिन तारीफों के लिए ही, बाल्कि इसके बाहर चलने के दृश्यों को लिया जाता है। इस आरओब्रिज पर आठ घंटे के भीतर दो सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें गाड़ियाँ डिवाइडर से टक्कराकर पलट गईं। गरीबत रही कि इन हादसों में किसी की जान नहीं गई, लेकिन पुल की निर्माण गुणवत्ता और डिजाइनिंग पर गंभीर सवाल ज़रूर खड़े हो गए हैं।

बिना नौकरी किए 12 साल तक आरक्षक को मिलता रहा वेतन

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश पुरुलिया अनेक एक आरक्षक को पिछले 12 सालों से बिना किए एक दिन आरक्षक को लिए वेतन देती रही है। इस आरक्षक को भर्ती के बाद बुनियादी प्रशिक्षण के लिए भोपाल पुरुलिया लाइन से सामर भेजा गया था। आरक्षक विद्यासारण अन्त अपने घर चला गया। तबसे सरकार दूर महीने तय समय पर उपर्युक्त तथा वेतन भेजती रही। 10 साल बाद एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल में हुई थी। बैच के अधिकारियों के क्रियाकलापों के प्रशिक्षण के बाद जाने के बाद उसने एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल पुरुलिया लाइन में वापस पहुंचा तो अधिकारियों ने उसकी जांच नहीं की। कागजों में उसकी नियुक्ति पुरुलिया लाइन भोपाल में दिखायी रही। इस तरह बगैंहों की रिकार्डों को उत्तर दर्शाया जाएगा। जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 में विद्यासारण के लिए बालों वेतन भेजती रही। 10 साल बाद एक आरक्षक की नियुक्ति भोपाल में हुई थी। बैच के अधिकारियों के क्रियाकलापों के प्रशिक्षण के बाद जाने के बाद उसने एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल लाइन में वापस पहुंचा तो अधिकारियों ने उसकी जांच नहीं की। कागजों में उसकी नियुक्ति पुरुलिया लाइन भोपाल में दिखायी रही। इस तरह बगैंहों की रिकार्डों को उत्तर दर्शाया जाएगा। एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल में हुई थी। बैच के अधिकारियों के क्रियाकलापों के प्रशिक्षण के बाद जाने के बाद उसने एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल पुरुलिया लाइन में वापस पहुंचा तो अधिकारियों ने उसकी जांच नहीं की। कागजों में उसकी नियुक्ति पुरुलिया लाइन भोपाल में दिखायी रही। इस तरह बगैंहों की रिकार्डों को उत्तर दर्शाया जाएगा। एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल में हुई थी। बैच के अधिकारियों के क्रियाकलापों के प्रशिक्षण के बाद जाने के बाद उसने एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल पुरुलिया लाइन में वापस पहुंचा तो अधिकारियों ने उसकी जांच नहीं की। कागजों में उसकी नियुक्ति पुरुलिया लाइन भोपाल में दिखायी रही। इस तरह बगैंहों की रिकार्डों को उत्तर दर्शाया जाएगा। एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल में हुई थी। बैच के अधिकारियों के क्रियाकलापों के प्रशिक्षण के बाद जाने के बाद उसने एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल पुरुलिया लाइन में वापस पहुंचा तो अधिकारियों ने उसकी जांच नहीं की। कागजों में उसकी नियुक्ति पुरुलिया लाइन भोपाल में दिखायी रही। इस तरह बगैंहों की रिकार्डों को उत्तर दर्शाया जाएगा। एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल में हुई थी। बैच के अधिकारियों के क्रियाकलापों के प्रशिक्षण के बाद जाने के बाद उसने एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल पुरुलिया लाइन में वापस पहुंचा तो अधिकारियों ने उसकी जांच नहीं की। कागजों में उसकी नियुक्ति पुरुलिया लाइन भोपाल में दिखायी रही। इस तरह बगैंहों की रिकार्डों को उत्तर दर्शाया जाएगा। एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल में हुई थी। बैच के अधिकारियों के क्रियाकलापों के प्रशिक्षण के बाद जाने के बाद उसने एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल पुरुलिया लाइन में वापस पहुंचा तो अधिकारियों ने उसकी जांच नहीं की। कागजों में उसकी नियुक्ति पुरुलिया लाइन भोपाल में दिखायी रही। इस तरह बगैंहों की रिकार्डों को उत्तर दर्शाया जाएगा। एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल में हुई थी। बैच के अधिकारियों के क्रियाकलापों के प्रशिक्षण के बाद जाने के बाद उसने एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल पुरुलिया लाइन में वापस पहुंचा तो अधिकारियों ने उसकी जांच नहीं की। कागजों में उसकी नियुक्ति पुरुलिया लाइन भोपाल में दिखायी रही। इस तरह बगैंहों की रिकार्डों को उत्तर दर्शाया जाएगा। एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल में हुई थी। बैच के अधिकारियों के क्रियाकलापों के प्रशिक्षण के बाद जाने के बाद उसने एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल पुरुलिया लाइन में वापस पहुंचा तो अधिकारियों ने उसकी जांच नहीं की। कागजों में उसकी नियुक्ति पुरुलिया लाइन भोपाल में दिखायी रही। इस तरह बगैंहों की रिकार्डों को उत्तर दर्शाया जाएगा। एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल में हुई थी। बैच के अधिकारियों के क्रियाकलापों के प्रशिक्षण के बाद जाने के बाद उसने एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल पुरुलिया लाइन में वापस पहुंचा तो अधिकारियों ने उसकी जांच नहीं की। कागजों में उसकी नियुक्ति पुरुलिया लाइन भोपाल में दिखायी रही। इस तरह बगैंहों की रिकार्डों को उत्तर दर्शाया जाएगा। एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल में हुई थी। बैच के अधिकारियों के क्रियाकलापों के प्रशिक्षण के बाद जाने के बाद उसने एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल पुरुलिया लाइन में वापस पहुंचा तो अधिकारियों ने उसकी जांच नहीं की। कागजों में उसकी नियुक्ति पुरुलिया लाइन भोपाल में दिखायी रही। इस तरह बगैंहों की रिकार्डों को उत्तर दर्शाया जाएगा। एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल में हुई थी। बैच के अधिकारियों के क्रियाकलापों के प्रशिक्षण के बाद जाने के बाद उसने एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल पुरुलिया लाइन में वापस पहुंचा तो अधिकारियों ने उसकी जांच नहीं की। कागजों में उसकी नियुक्ति पुरुलिया लाइन भोपाल में दिखायी रही। इस तरह बगैंहों की रिकार्डों को उत्तर दर्शाया जाएगा। एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल में हुई थी। बैच के अधिकारियों के क्रियाकलापों के प्रशिक्षण के बाद जाने के बाद उसने एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल पुरुलिया लाइन में वापस पहुंचा तो अधिकारियों ने उसकी जांच नहीं की। कागजों में उसकी नियुक्ति पुरुलिया लाइन भोपाल में दिखायी रही। इस तरह बगैंहों की रिकार्डों को उत्तर दर्शाया जाएगा। एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल में हुई थी। बैच के अधिकारियों के क्रियाकलापों के प्रशिक्षण के बाद जाने के बाद उसने एक आरक्षक को नियुक्ति भोपाल पुरुलिया लाइन में वापस पहुंचा तो अधिकारियों ने उसकी जांच नहीं की। कागजों में उसकी नियुक्ति पुरुलिया लाइन भोपाल में दिखायी रही। इस तरह बगैंहों की रिकार्डों को उत्तर दर

विचार

पुलिस स्टेशनों में सड़ते वाहनों की समस्या

भारत में अपराधों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया में वाहन अक्सर महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। कार, रॉटरसाइकिल, ट्रक या अन्य साधन अपराध के दृश्य का एक अभिन्न हिस्सा हो सकते हैं। पुलिस द्वारा इन वाहनों को जब्त कर लिया जाता है और साक्ष्य के रूप में अदालत में पेश किया जाता है। हालांकि, इन जब्त वाहनों का प्रबंधन और रखरखाव एक ऐसी समस्या बन चुका है, जो न केवल पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द है, बल्कि पर्यावरण, संसाधनों और सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक गंभीर चुनौती बन गया है। पुलिस स्टेशनों और मालखानों में ये वाहन वर्षों तक सड़ते रहते हैं, जिससे न केवल जगह की कमी होती है, बल्कि यह व्यवस्था की नाकामी को भी उजागर करता है।

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) की धारा 102 के तहत पुलिस को ऐसे वाहनों को जब्त करने का अधिकार है, जो अपराध से संबंधित हों। इन वाहनों को मालखाने या पुलिस स्टेशन के परिसर में रखा जाता है, जब तक कि मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। हालांकि, सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत में न्यायिक प्रक्रिया अक्सर लंबी चलती है। कई मामलों में, सुनवाई में वर्षों लग जाते हैं और इस दौरान जब्त वाहन पुलिस स्टेशनों में खड़े रहते हैं। बारिश, धूप और धूल के संपर्क में रहने के कारण ये वाहन खराब हो जाते हैं और धीरे-धीरे कबाड़ में तब्दील हो जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इससे भारत को हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है।

कई मामलों में, ये वाहन उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति होते हैं, जो शायद निर्दोष हों या जिनके खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिले। उदाहरण के लिए, एक ऑटो-रिकशा चालक या टैक्सी ड्राइवर के लिए उसका वाहन उसकी आजीविका का मुख्य साधन होता है। जब ऐसे वाहन लंबे समय तक पुलिस हिरासत में रहते हैं, तो मालिक की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। यह सामाजिक असमानता को और बढ़ाता है क्योंकि अधिकांश प्रभावित लोग निम्न या मध्यम वर्ग से होते हैं। इसके अलावा, पुलिस स्टेशनों के बाहर खड़े वाहन अक्सर आस-पास के निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। ये वाहन सड़कों को अवरुद्ध करते हैं, पार्किंग की समस्या पैदा करते हैं और कई बार असामाजिक तत्वों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि वाहनों के महत्वपूर्ण हिस्से, जैसे बैटरी, टायर या इंजन के पुर्जे गायब हो जाते हैं। यह न केवल भृष्टाचार को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जो न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करता है।

इस समस्या के समाधान के लिए नीतिगत और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। पहला कदम यह हो सकता है कि वाहनों की जब्ती और रिहाई की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया

अफ्रीकी देश माली में तीन भारतीयों के अपहरण के आतंकी व वैश्विक मायने को ऐसे समझिए

कमलेश पांडे

अफीकी देश माली में तीन भारतीयों के अपहरण के आतंकी मायने स्पष्ट हैं और साफ तौर पर भारत सरकार को आगाह करने वाले हैं। आखिर यह महज संयोग है या फिर कोई अभिनव प्रयोग, कि एक तरफ गत 1 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम अफीका के देशों की यात्रा पर रवाना हुए, और दूसरी तरफ पश्चिमी अफीका के ही पश्चिमी माली में गत 1 जुलाई को ही कई जगहों पर आतंकवादी हमले हुए। इन हमलों के बाद तीन भारतीय नागरिकों को बंधक भी बना लिया गया है। कहना न होगा कि जिस तरह से इस बारदात में शक की सुई कुयात वैश्विक आतंकवादी संगठन अलकायदा समर्थित मुखौटा संगठन नुसरत अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन यानि जेएनआईएम की ओर धूम रही है, वह चिंता का विषय है।

की मांग की है। बताया गया है कि भारतीय द्वावास बमाको में स्थानीय अधिकारियों और फैक्ट्री प्रबंधन के संपर्क में है। उसके द्वारा पीड़ितों के परिवारों को लगातार जानकारी दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि नुसरत अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन यानि जेएनआईएम एक कट्टर इस्लामिक संगठन है, जिसका मकसद एक कट्टर इस्लामिक शासन की नींव रखना है। इयाद आग घाली और अमादौ कूफा इस संगठन का नेतृत्व करते हैं। बताया गया है कि इयाद एक दुआरेग जातीय नेता है जबकि कूफा फुलानी, स्थानीय मुस्लिम समुदाय का प्रभावशाली इस्लामी उपदेशक हैं। इस प्रकार दोनों की घातक साझेदारी से पता चलता है कि जेएनआईएम सिर्फ इस्लामिक कट्टरता ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को भी रणनीति का हिस्सा बनाता है।

उल्लेखनीय है कि जेनरनार्इएम ने खुद को अल-कायदा के आधिकारिक प्रतिनिधि के तौर पर स्थापित किया है। इससे साफ है कि यह भी उसी तरह का खुराकाती संगठन है। समझा जाता है कि जब से अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम जगा है, तब से आतंकियों की चांदी हो गई है और वे अपना पुनः विस्तार कर रहे हैं। हालांकि, पिछले कुछ सालों में इसके कुछ बयानों में अल-कायदा का जिक्र नहीं होने से अटकले हैं कि संगठन अपनी वैचारिक दिशा में बदलाव पर विचार कर रहा है।

जानकारों के मुताबिक, जेनर्नाईट्रोन के पास इस समय तकरीबन 5-6 हजार लड़के हैं। इसकी संरचना काफी विकेंद्रित है, जिसकी वजह से ये अलग-अलग स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढाल लेता है। यह संगठन अलकायदा की फैंचाइज शैली में काम करता है। जिसका अभिप्राय यह हुआ कि विभिन्न इलाकों में इसके स्थानीय कमांडर्स स्वतंत्र रूप से फैसले लेते हैं।

गौरतलब है कि जेएनआईएम ना सिर्फ हथियारों से सुअज्जित संगठन है, बल्कि यह उन इलाकों में भी शासन करता है, जहां पर सरकार की पहुंच कमज़ोर है। यह इस्लाम के आधार पर अलग-अलग गांवों से समझौता करता है और इस्लामिक कानून को मानने वाले गांवों की सुरक्षा करता है। इसके बदले संगठन जकात (मजहबी टैक्स) वसूल करता है। वहां पर यह इस्लामी शरीया कानून भी लागू करता है, जिसमें महिलाओं की पढ़ाई पर सख्त प्रतिबंध है।

बताते चलें कि पिछले एक दशक में साहैल क्षेत्र, खास तौर पर माली, बुर्किना फासो और नाइजर कृष्यात आतंकवाद का केंद्र बन गया है। समझा जाता है कि यूरोपीय देश फांस और संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नकारात्मक भूमिका को लेकर यहाँ नाराजगी है। स्थानीय सरकारों की तानाशाह रवैये ने भी स्थिति को और ज्यादा खराब ही किया है। जेएनआईएम ने लोगों के इसी गुस्से और सरकार के नकारेपन का फायदा उठाया है और अपने प्रभाव का आशातीत विस्तार किया है।

उल्लेखनीय है कि मई 2025 में इसने बुर्किना फासो के डजीबो में हमला कर लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, जेएनआईएम अब पश्चिमी माली से लेकर बेनिन, नाइजर और यहां तक कि नाइजीरिया की सीमा तक एक %जिहादी बेल्ट% बनाने में जुटा हूँआ है। यह बेल्ट संगठन के नियंत्रण वाले इलाकों को जोड़ता है, जहां वह टैक्स बसूलने का साथ साथ शरीया कानून के तहत शासन करता है।

बताया जाता है कि अफ्रीका महादेश के विभिन्न देशों में अमेरिका, रूस, इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान के अतिरिक्त भारत और चीन की दिलचस्पी बढ़ रही है। इसलिए पारस्परिक प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को मात देने व उनकी राहों में काटे बोने के लिए ऐसे ही आतंकी समूहों को गुप्त मदद दी जाती है। इसलिए अफ्रीकी देश माली की सरकार को तीनों अपहृत भारतीयों की बरामदगी सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही इस अपहरण के आतंकी मायने वैश्विक नजरिए से विश्लेषित करते हुए एहतियाती उपाय भी किया जाना चाहिए। अन्यथा विकास अवरुद्ध होगा और विनाश तेज ! जो किसी के हक में नहीं होगा। वहीं, भारत सरकार को चाहिए कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ, जी- 7, ब्रिक्स, जी-20 आदि सभी मंचों पर विकसित देशों की मदद से आतंकी उत्पादक देशों की बढ़ती खुराफाती प्रवृत्ति पर लगाम लगवाए, अन्यथा फैसला आँन द स्पॉट कर देने की नसीहत दे, क्योंकि बिना भय होहिं न प्रीति बाली कहावत सब जगह पर लाग होती है।



बताया जाता है कि जेनर्नाईएम वर्ष 2017 में अस्तित्व में तब आया था, जब इसने पश्चिम अफ्रीका में सक्रिय चार बड़े जिहादी गुटों – अंसार दिन, अल-मुराबितून, अल-कायदा इन द इस्लामिक मध्येरेब यानी एक्यूआईएम की साहेल ब्रांच और मकना कतीवात मसिना ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की। चूंकि यह भी एक कट्टर इस्लामिक संगठन है, जिसका मकसद एक कट्टर इस्लामिक शासन की नींव रखना है। इसलिए इसी पर भारतीयों के अपहरण का शक है। इस अजीबोगरीब अफ्रीकी आतंकी अपहरण की घटना के मायने स्पष्ट हैं, जो इस बात का इशारा करते हैं कि भारत विरोधी अमेरिका-चीन-पाकिस्तान-ईरान की आतंकी पकड़ कितनी ज्यादा है। कारण कि उनके इशारे के बिना भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के ठीक पहले ऐसी दुस्साहसिक कार्रवाई करने की जुर्त किसी आतंकी संगठन में हो ही नहीं सकती है। इसलिए भारत सरकार को सजग हो जाना चाहिए और ऐसी वारदातों की जांच करनी चाही जाए।

के बाद त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया देने की गुंजाइश तलाशी जानी चाहिए। अन्यथा सम्बद्धित देश के मिलोभगत से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रास जानकारी के मुताबिक, यह हमला कायेस में डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में हुआ, जहां हथियारबंद लोगों के एक समूह ने साइट में प्रवेश किया और किए गए ऑपरेशन सिंदूर के घातक प्रभावों के डर से आतंकियों ने इस घटना को सीधी जिम्मेदारी नहीं ली, क्योंकि इसमें ही भारतीयों का अपहरण किया गया था। यूं तो भारत सरकार ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। भारत सरकार ने माली सरकार से बंधकों की तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने

जाम के झाम से मुक्ति के हों पुरखा इंतजाम

डॉ. आशीष वशिष्ठ

तक का रास्ता महज 40 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताया था। निश्चित रूप से इस दुर्घटना और हजारों लोगों के बंटों जाम में फंसे रहने के मामले में जहां एनएचएआई की तरफ से माफी मांगने की जरूरत थी, वहीं उसने दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिये दोष लोगों पर लगाते हुए असंवेदनशील बयान दे डाला। 30 जून को अदालत में जवाब देते हुए एनएचएआई के वकील ने कहा कि लोग बिना जरूरी काम के इतनी सुबह घर से बाहर निकलते ही क्यों हैं? एनएचएआई की इस टिप्पणी ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया। उनके इस बयान को सुनकर लोगों को ऐसा लग रहा है कि एनएचएआई घटना की जिम्मेदारी लेने से बच रहा है और घटना के लिए आम लोगों को ही दोषी बताने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी एनएचएआई के रुख को कठोर और संवेदनशील बताया है, जो जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करने वाला है। विवाद बढ़ने पर एनएचएआई ने कहा कि यह टिप्पणी अथॉरिटी के आधिकारिक विचारों को नहीं दर्शाती।

देश में जहां एक तरफ ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए सड़कों, हाई-वेज और एक्सप्रेस-वेज को बनाने का काम जोरों-शोरों पर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे शहर भी हैं, जो अंदरूनी ट्रैफिक से काफी ज्यादा परेशान हैं। असल में, ट्रैफिक जाम की समस्या से बड़े ही नहीं बल्कि छोटे शहर भी जूझते हैं। लेकिन बड़े शहरों में यह एक संकट का रूप लेने लगा है। एक जानकारी के मुताबिक एक घंटे जाम में एक लीटर ईंधन बबांद होता है। जितनी ईंधन की खपत होगी, उतना ही ज्यादा सीओटू उत्पर्जन भी होगा, जो



पर्यावरण और प्रदूषण के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक होता है। एक अनुमान के अनुसार, महानगरों में और हाईवे पर देश में हर साल लगाने वाले ट्रैफिक जाम से हर साल तक रीबन 1.4 लाख करोड़ रुपये तक का नुकसान हो रहा है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 के अनुसार, देश में कोलकाता का ट्रैफिक सबसे धीमा है। बैंगलुरु ने इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जगह बनाई है। कमोबेश ऐसे हालात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, चंडीगढ़, गुरुग्राम, लखनऊ, जयपुर, कानपुर, अपृतसर, अहमदाबाद, वाराणसी और देश के अन्य शहरों में भी आये हैं।

बीमारी, डिहाइड्रेशन, फीवर, घबराहट, सीने में दर्द आदि बीमारियों का सामना करना पड़ता है गंभीर मरीज लंबे समय तक जाम में फंस जाते हैं तो उसकी मौत भी हो सकती है। 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाया करते हुए कहा था कि यदि अब जाम में एंबुलेंस फंसी तो इसे अपराध माना जाएगा और मरीज को नुकसान पहुंचाने के तहत कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके स्थिति में कोई खास फर्क दिखाया नहीं देता।

इसमें दो गाय नहीं कि सड़कों के नेटवर्क सुधारने के लिए लागू होने वाली नीति बनाई जाएगी ताकि ये नियमों के अनुसार ही लागू हों।

महानगरों और शहरों के हैं। डाक्टरों के अनुसार, जाम में फंसने वालों को अक्सर ल्लड पेश्यर बढ़ाने वर्नभारत संघ की से उपभोक्ताओं के समय व धन को बचत हुई है त उद्योग-व्यापार को भी गति मिली है। लेकिन इससे जड़ी तमाम क्रियांतियां भी सामने आई हैं। सदकों

के त्रुटिपूर्ण डिजाइन व निर्माण में चूक को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। वहाँ अकसर बड़ी सड़कों और राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण के दौरान अंतहीन असुविधा भरतीय यात्रियों के लिए रोजमर्या के अनुभव हैं। अधिकांश साइटों पर निर्माण से जुड़ी, यात्रियों के अनुकूल सर्वोत्तम परंपराओं को अपनाना और यातायात में व्यवधान को कम से कम करना सनिश्चित नहीं किया जाता है।

करना तुमाना पहा किया जाता है। जानकारों के मुताबिक, जाम की समस्या को खत्म करने के लिए सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना होगा। इसके अलावा लोगों को कार पूलिंग के लिए जागरूक करना होगा जिससे सड़क पर वाहनों की संख्या को कम किया जा सके। सड़क पर जाम का एक बड़ा कारण जगह-जगह कट का होना भी है। पैदल और छोटे वाहनों के आवागमन के लिए मुख्य सड़कों के साथ सर्विस रोड बनाए जाने से भी जाम की समस्या से निजात पाया जा सकता है। जिन स्थानों पर घनी आबादी के चलते सर्विस रोड नहीं बनाए जा सकते। वहाँ एलिवेटेड रोड, अंडरपास और फ्लाईओवर आदि यहाँ सिर्फ बिल्कुल जरूरी हैं।

जाम से जूझते शहरों में सड़कों की भीड़भाड़ कम करने के लिए केंद्र सरकार सरकार ने राज्यों की राजधानियों समेत दस लाख से अधिक आबादी वाले 94 शहरों में जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए रिंग रोड, बाईपास समेत अन्य उपाय करने की योजना बनाई है। यूरी में लोगों को जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए पुलों, रिंग रोड और बाईपास का जाल बिछाया जाएगा। इनके निर्माण पर लोक निर्माण विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 6124 करोड़ रुपए का बजट खच करेगा। सीएम योगी के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी की ओर से यह खाका खींचा गया है।

रायपुर में किसान-जवान-संविधान सभा कल

पायलट बोले-प्रदेश में कानून व्यवस्था बद से बदतर

सचिन ने कहा-बारिश है, बादल हैं, लेकिन काग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 7 जुलाई को काग्रेस किसान-जवान-संविधान सभा कल है। इसे लेकर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि, बारिश है, बादल हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। इस कार्यक्रम से काग्रेस की भविष्य की तेजाएँ पर चर्चा होगी।

उहोंने कहा कि एक दिशा तय की जाएगी कि किस दिशा में काग्रेस पार्टी को चलना है। परंतु सभा कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। प्रदेश में जनता परेशान है। हर मर्याद पर सकार को धरने की रणनीति तेवर की जाएगी।

साथ ही सचिन पायलट ने रविवार को साइंस कॉलेज में जनता परेशान होने की जायजा लिया। मंच, पंडाल, सुरक्षा और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिवक्ष डॉ.



चरणदाम महंत और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे।

प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने बायोटेक्नोलॉजी में कहा कि, यह सभा सिफार कार्यक्रम में नहीं, बल्कि लोकवान और संविधान को बचाने की दिशा में एक कदम है। दिशा निर्देश तय होंगे आगामी समय में मलिकाजुन खड़ग का एक दिवसीय दौरा है। कार्यकर्ता पूरे

उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं।

काग्रेस की जनसभा के बाद के बायोटेक्नोलॉजी को बैठक होगी। जिस पर सचिन पायलट ने कहा कि जनसभा के बाद काग्रेस पार्टी की बैठक होगी। दिशा निर्देश तय होंगे आगामी समय में काग्रेस को धरने की तरफ लगेंगे।

पायलट ने कहा कि इस बैठक में उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं।



कि हम किसी पर भी कमेट नहीं करें। बीजेपी को जो मर्जी करना है करे, लेकिन प्रदेश उनके हाथ में है, तो जबाबदहीं उनकी बताती है। पायलट ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बदल है, जनता परेशान है। सकार की व्यवस्थाओं के ऊपर ये लोगों का विश्वास उठ रहा है। बीजेपी जबाब नहीं देती। उनके प्रधानमंत्री निरेश घूमते हैं।

राज्य में जनता परेशान है। बीजेपी डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बहु पर स्थान को बोगमुक्त किया है।

बीजेपी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बदल है, तो यह सोचने वाली बात है। इससे स्पष्ट है कि संघर्ष व्यवस्था बदल रही है। बीजेपी लोअर कोर्ट ने दोनों को 7 साल के सम्राट कारावास और 1 हजार जुर्मानी की सजा सुनाई ही।

ससुराल में महिला ने खुद को लगाई आग, पति-ससुर दोषमुक्त



हाईकोर्ट बोला- गुस्से में कहे गए शब्द, सुसाइड के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता

पति और ससुर उसे अपशब्द कहकर अपमानित करते थे और चरित्र पर शंका करते थे। ससुराल वालों की तिरकरपूर्ण भाषा के कारण उसने खुद पर कोरेसिन डालकर आग लगाई है।

मुतका के मारा-पिता और भाई ने भी अपने बचपन में बताया कि पति-पत्नी के बीच अक्सर झड़ूँ होते थे और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।

अपीलकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट में तर्क दिया कि घटना से ठीक पहले किसी भी प्रकार की तुरंत उकसाना वाली या उत्प्रेक बात नहीं थी। बीजेपी लोअर कोर्ट ने दोनों को 7 साल के सम्राट कारावास और 1 हजार जुर्मानी की सजा सुनाई ही।

घटना 13 साल पहले की है। जब एक मालिना ने केतेसिन डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया था। मौत से पहले अपने बचाने में मालिना ने कहा था कि ससुराल वालों की टिप्पणी और अपशब्द आधार नहीं है। बीजेपी लोअर कोर्ट ने दोनों को 7 साल के सम्राट कारावास और 1 हजार जुर्मानी की सजा सुनाई ही।

अधियोजन पक्ष आमहत्या के लिए जरूरी दुष्प्रेरण (उकसान) सिद्ध करने वाले यह सावित होता है कि आरोपियों ने मृतक का प्रताड़ित किया और उसे आमहत्या के लिए विवाह किया।

जस्टिस बिमु दाम गुरु ने धारा 306 आईपीरी की व्याप्ति करते हुए कहा कि आमहत्या के लिए दुष्प्रेरण (उकसान) सिद्ध करने वाले यह सावित होता है कि आरोपियों ने मृतक का प्रताड़ित किया और उसे आमहत्या के लिए विवाह किया।

जानवृकार मजबूर किया। काट ने स्पष्ट किया कि 'शादी' को 12 साल छोड़ कर लें। इसलिए धारा 113 के तहत 7 सालों के अंतर्वाले भर्ती कराया गया।

धारा 2014 को उकसान की मौत हो गई। मृतक ने खाली वाली बातों से बदल दिया है। अरोपी कोर्ट ने उकसान की मौत हो गई।

अरोपी के मुताबिक महिला के

पिकअप-बस ने बाइक सवारों को रोंदा, तीन लोगों की मौत

मीडिया ऑडीटर, कोरबा (निप्र)। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मालिना दर्ज कर लिया है। दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वाहन को रुटर कार डाइवर को गिरफतार कर लिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, अजय की घटनास्थल पर हो गई। जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 1 युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।

बीजेपी घटना वीपका थाना क्षेत्र के रेनपुर की है। वहां रविवार सुबह बस और बाइक की आमने-सामने टकराए हो गई। हावसे में एक युवक की मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक, अजय की घटनास्थल पर हो गई। जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 1 युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई।

उक्से के मुताबिक, अजय की घटनास्थल पर हो गई। जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 1 युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई।

मिली जानकारी के अनुसार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई।

मिली जानकारी के अनुसार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई।

मिली जानकारी के अनुसार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई।

मिली जानकारी के अनुसार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई।

मिली जानकारी के अनुसार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई।

मिली जानकारी के अनुसार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई।

मिली जानकारी के अनुसार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई।

मिली जानकारी के अनुसार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई।

मिली जानकारी के अनुसार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई।

मिली जानकारी के अनुसार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई।

मिली जानकारी के अनुसार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई।

मिली जानकारी के अनुसार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई। घायल के बायोटेक्नोलॉजी के रुटर की जान चली गई।

